

धनुमानतः कुल कितनी कात्रा में गाय तथा बछड़े के चमड़े का निर्यात किया जायेगा तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राय होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जाज) : (क) तथा (ख). वारिण्डिक जानकारी तथा अकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता गाय तथा बछड़े की खालों के अलग-अलग निर्यात आंकड़े प्रकाशित नहीं करते। इसके प्रतिरिक्त, गाय तथा बछड़े की खालों के निर्यात को प्रोत्साहन देना, सरकार की नीति नहीं है और इसलिए उन्हें, तकनीकी विकास के महानिदेशक के परामर्श से "गुरावगुण के आधार पर" निर्यात के लिये सूची में रखा गया है।

हिन्दी दैनिक "भवन्तिका" को दिया गया
अखबारी कागज

352. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहन प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन द्वारा प्रकाशित किये जा रहे हिन्दी दैनिक "भवन्तिका" की प्रतियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इसे अखबारी कागज का कितना कोटा दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार का इस आरोप की जांच करने का विचार है कि उपरोक्त समाचारपत्र के मालिक ने अखबारी कागज को काले बाजार में बेचा और छापी जा रही प्रतियों की संख्या बढ़ा कर बताई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री वर्षधर सिंह) : (क) उज्जैन से प्रकाशित होने वाले दैनिक "भवन्तिका" के प्रमाणों ने 1968, 19 9 तथा 1970 के

वर्षों में इसकी क्रमशः 5407, 7756 तथा 8402 खपत संख्या होने का दावा किया।

(ख) इसको पिछले दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज का निम्नलिखित कोटा अलॉट किया गया :—

		मात्रा-टनों में
1. अप्रैल 1969-मार्च 1970		31.06
2. अप्रैल 1970-मार्च 1971		38.43 (लोक समा के मध्या-वधि चुनावों के सम्बन्ध में 1. 16 टन समेत)।

(ग) "भवन्तिका" के मालिक द्वारा अखबारी कागज को काले बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, जुलाई 1968 में एक शिकायत मिली थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पत्र ने खपत संख्या का बढ़ा चढ़ा कर दावा किया है। मामले की जांच हो रही है।

मध्य प्रदेश में डाकुओं के आतंक पर
नियंत्रण का प्रस्ताव

353. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के डाकू आतंकित क्षेत्रों के निवासियों को डाकुओं के आतंक से छुटकारा दिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को भविष्य में किस प्रकार के निर्देश तथा सहयता देने का विचार है ?